आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, बुधवार 24 जून 2026
■ वर्ष : 5 ■ अंक : 204
■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

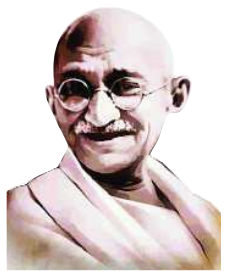

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

अवंतिका गैस लाइन फटी, 3 राहगीर झुलसे

पेज-2

महाकाल मंदिर में 142 करोड़ रुपए की आय

पेज-5

किराए पर स्वीपिंग मशीन और ठेकेदारों को भुगतान नहीं

पेज-6

पहली बारिश में ही हुआ लबालब...

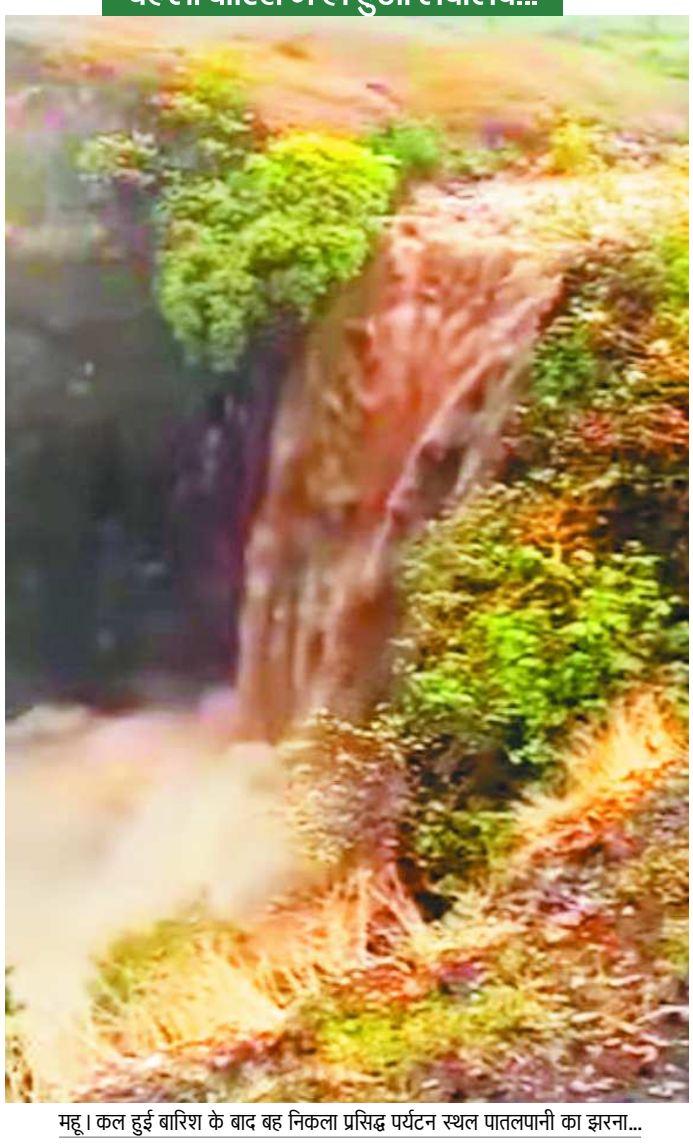

महू। कल हुई बारिश के बाद बह निकला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातलपानी का झरना...

आज गहराया इंदौर में जलसंकट

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में आज पूरी क्षमता से जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। बिजली फाल्ट के कारण नर्मदा के पंप बंद करने पड़े, जिससे ओवरहेड टंकियां पूरी तरह नहीं भर पाईं। इसके चलते इंदौर की 73 टंकियों से जलप्रदाय बाधित रहेगा।

मेन पंपिंग लाइन बंद होने से बिगड़ी व्यवस्था : बिजली फाल्ट मंगलवार 23 जून को दोपहर करीब एक बजे हुआ था। इसके कारण 1700 मिमी व्यास की मेन पंपिंग लाइन के सभी पंप बंद करने पड़े। लाइन सुधारने के बाद करीब साढ़े तीन बजे से पाइप लाइन में दोबारा दबाव बनना शुरू हुआ। इसके बाद दोपहर बाद करीब पौने पांच बजे

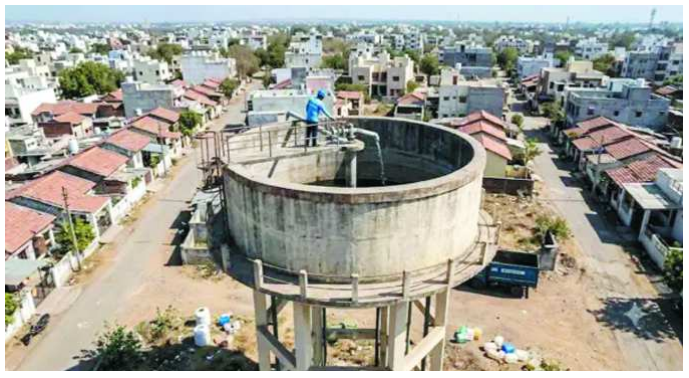

ओवरहेड टंकियों को भरने का काम शुरू किया गया। स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया कि सभी टंकियों को उनकी क्षमता से करीब 30 सेमी कम भरा जाएगा। इसका असर बुधवार की जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ेगा।

पटवारी की रिश्वत का रेट एक बीघा का एक लाख रुपए, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में राजस्व से जुड़े कामों में भारी देरी हो रही है। इसकी बड़ी वजह भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। एक छोटे से काम के लिए पटवारी ने 2 लाख रुपए मांग रहा है। यह शिकायत मंगलवार को सीधे कलेक्टर तक पहुंची, जिसके बाद तुरंत पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया।

इंदौर में राजस्व कामों को लेकर लंबित केस बढ़ रहे हैं। इन्हें पूरा कराने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा लगातार मीटिंग ले रहे हैं। अधिकारियों को फटकार लेकर दुलार सब कुछ हो रहा है, लेकिन निचले स्तर पर महकमा सुनने को तैयार नहीं है। अब एक पटवारी की मांग से रिश्वत का रेट तक सामने आ गया है। बात सनावदिया गांव की है। यहां पर फरियादी मोहन डाबी की दो बीघा जमीन है। तहसीलदार से आदेश होना था, वह हो गया। लेकिन इस आदेश को अमल करने के लिए पटवारी अनुशीलन जोसेफ ने उनसे दो लाख की मांग की। इसके लिए वह लगातार उनसे मिला और हर बार कहा कि दो लाख दो फिर अमल करेंगे।

कलेक्टर ने हाथों-हाथ किया सस्पेंड

कलेक्टर शिवम वर्मा के पास यह शिकायत पहुंची। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम अजय शुक्ला से जानकारी मांगी गई। पटवारी जोसेफ की और भी शिकायतें थीं, एसडीएम ने सारी जानकारी कलेक्टर को दे दी। इसके बाद कलेक्टर ने हाथों-हाथ पटवारी को सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसे सहन नहीं किया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

- लखनऊ अग्निकांड : एलडीए की जांच में 18 अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए
- भरत तिवारी एनकाउंटर : जगदीशपुर SDPO राजेश वर्मा को हटाया गया
- मुंद्रा पोर्ट 3000 किलो ड्रग्स केस : ED ने हरप्रीत तलवार के पांच ठिकानों पर छापे मारे
- सुपरकंप्यूटर की रेस में चीन नंबर-1, 2017 के बाद पहली बार अमेरिका को पछाड़ा
- अमेरिका : लाइब्रेरी में घुसकर 18 साल के लड़के ने की फायरिंग, 2 लोगों की मौत
- बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान आज से चीन के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे
- ओडिशा सरकार आज शहरी जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेगी
- राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन
- फीफा वर्ल्ड कप : पुर्तगाल ने दर्ज की एकतरफा जीत

पार्षद दल की राय को नहीं दिया गया महत्व

नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर कांग्रेस में बवाल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद पर सोनिला मिमरोट की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। नियुक्ति के दूसरे ही दिन पार्टी के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। शहर कांग्रेस के प्राथमिक सचिव राजेश मेवाड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि विधानसभा-1 क्षेत्र के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफों की चेतावनी दी है।

राजेश मेवाड़ा ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि संगठन ने लगातार वरिष्ठ और सक्रिय पार्षदों की उपेक्षा की है। उनका कहना है कि इस फैसले से जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं और संगठन में निराशा का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में वरिष्ठ पार्षद फौजिया शेख अलीम, रुबीना इकबाल खान और विनीतिका (दीपू) यादव के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में चर्चा में थे। संगठन और निगम के कई नेताओं का मानना था कि अनुभव और

वरिष्ठता के आधार पर इन्हीं में से किसी एक को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके बावजूद प्रदेश संगठन ने पहली बार पार्षद बनी सोनिला मिमरोट के नाम पर मुहर लगा दी।

अनुभवी पार्षदों को दरकिनार करना उचित नहीं : नियुक्ति के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी वरिष्ठपार्षद विनीतिका (दीपू) यादव के निवास पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि संगठन इसी तरह मनमाने निर्णय लेता रहा और वरिष्ठ पार्षदों व जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती रही तो वे सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि निगम में वर्षों से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे अनुभवी पार्षदों को दरकिनार करना उचित नहीं है। विधानसभा-1 क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक क्रमांक-1 और 3 के 17 वार्ड अध्यक्ष, 17 वार्ड प्रभारी, 17 महिलावार्डप्रभारी, 5 ब्लॉक अध्यक्ष तथा शहर कांग्रेस के 7 पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफे की तैयारी में हैं। यदि संगठन स्तर पर जल्द संवाद नहीं हुआ तो यह विवाद और गहरा सकता है। नेता प्रतिपक्षकी नियुक्ति को लेकर शुरूहुआ यह विवाद कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी और गुटबाजी को खुलकर सामने ले आया है। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व नाराज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कैसे मनाता है।

पार्षद दल की राय को महत्व नहीं दिया गया

कांग्रेस की परंपरा रही है कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का चयन पार्षद दल की बैठक में किया जाता है और निर्वाचित पार्षद अपने नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन इस बार प्रदेश नेतृत्व ने सीधे नियुक्ति कर दी, जिससे कई पार्षद और पदाधिकारी खुदको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विरोध करनेवाले नेताओं का आरोप है कि पार्षद दल की राय को महत्व नहीं दिया गया और ऊपर से फैसला थोप दिया गया।

भाजपा कार्यसमिति में फिर वीआईपी एंट्री! पूर्व कांग्रेसियों को बड़ी जिम्मेदारी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● भाजपा की नई प्रदेश कार्यसमिति में 17 मंत्रियों और पूर्व कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिलीं। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और संगठनात्मक संतुलन पर सवाल उठे। करीब 11 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश कार्यसमिति घोषित कर दी है। लेकिन सूची सामने आते ही संगठन के भीतर एक पुरानी बहस फिर तेज हो गई है।

सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा में वर्षों से मेहनत करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं की तुलना में प्रभावशाली नेताओं और दल बदलकर आए चेहरों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? नई कार्यसमिति में प्रदेश सरकार के 17 मंत्रियों को जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे संगठन के भीतर कार्यकर्ता बनाम प्रभावशाली नेताओं की चर्चा तेज हो गई है।

पूर्व कांग्रेसियों को मिली बड़ी जगह- नई कार्यसमिति की सबसे चर्चित बात कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले नेताओं की मजबूत मौजूदगी रही। कभी भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले और भाजपा की नीतियों के मुखर आलोचक रहे कई नेता अब संगठन की सबसे प्रभावशाली इकाई का हिस्सा बन गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुरेश पचौरी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। वहीं छिंदवाड़ा के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना को भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन नेताओं को मिला स्थान- प्रदेश कार्यसमिति में कांग्रेस से भाजपा में आए कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, दीपक सक्सेना, अखंड प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ऐदल सिंह कंसाना, उदय प्रताप सिंह, रक्षा पिरोनिया, गिर्राज दंडोतिया, ओपीएस भदौरिया, इमरती देवी और महेंद्र सिंह सिसौदिया जैसे नाम प्रमुख हैं।

आरटीओ : गलती सिस्टम की, सजा जनता को

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● परिवहन विभाग ने अपनी सेवाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के नाम पर पूरी व्यवस्था आनलाइन तो कर दी, लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम की रीढ़ माने जाने वाले सर्वर को ठीक करने की जिम्मेदारी मानो भूल ही गया। नतीजा यह है कि सुविधा के दावे अब आवेदकों के लिए मुसीबत में बदलते जा रहे हैं।

नायता मुंडला स्थित आरटीओ कार्यालय में बीते चार दिन से सर्वर ठप पड़ा है, जिससे परमिट, फिटनेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल जैसी जरूरी प्रक्रियाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं।आवेदक परेशान हो रहे है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा।

परिवहन विभाग ने आवेदन से लेकर निराकरण तक सभी प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल पर आनलाइन कर दी है। दावा था कि इस प्रक्रिया के बाद आवेदकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पढ़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही काम हो जाएगा। सर्वर की परेशानी के कारण काम समय पर नहीं हो पा रहा है।

स्थिति यह है कि परिवहन विभाग में रोजाना हजारों आवेदन पहुंचते हैं, लेकिन सर्वर की सुस्ती और बार-बार ठप होने की समस्या के कारण काम आगे बढ़ने के बजाय फाइलें पेंडेंसी में दबती जा रही हैं। सबसे ज्यादा मार उन वाहन मालिकों और कमर्शियल चालकों पर पढ़ रही है, जिनकी रोजी-रोटी कमर्शियल वाहनों पर टीकी है। रिन्यूअल कराने वालों की परेशानी अलग है। विभागीय लापरवाही से सर्वर डाउन है, लेकिन समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पेनल्टी आवेदकों से ही वसूली जा रही है। यानी गलती सिस्टम की, सजा जनता को। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं में ओटीपी तक समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे आवेदक घंटों चक्कर काटने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं।

टैक्स चोरी रोकने के लिए निगम फिर लेगा जीआईएस सर्वे का सहारा

सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड भी होगा दुरुस्त, बिजली कंपनी को कमर्शियल बिल और निगम को आवासीय टैक्स चुका रहे लोग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में एक बार फिर नगर निगम प्रशासन की नजर जीआईएस सर्वे पर टिक गई है। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा यह प्रस्ताव अब फिर से सक्रिय हो गया है। राजस्व विभाग ने इस दिशा में फाइल आगे बढ़ाते हुए एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराने की प्रक्रिया को पुनर्जीवित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर और 29 गांवों में फैली संपत्तियों की वास्तविक स्थिति सामने लाकर संपत्तिकर से होने वाली आय को बढ़ाना है।

राजस्व बढ़ाने पर फोकस, टैक्स चोरी पर नजर- नगर निगम का मानना है कि शहर में कई ऐसी संपत्तियां हैं जो टैक्स नेटवर्क से बाहर हैं या गलत श्रेणी में दर्ज हैं। कई रिहायशी संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन टैक्स अभी भी आवासीय दर पर ही जमा किया जा रहा है। इसके अलावा खाली भूखंड और सरकारी जमीनें भी हैं जिनका सही आकलन नहीं हो पाया है। ऐसे में जीआईएस सर्वे को एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, जिससे इन सभी विसंगतियों को दूर किया जा सके। संपत्तियों का डिजिटल मैप बनाने की तैयारी प्रस्तावित जीआईएस सर्वे के तहत शहर की हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसमें भवन का क्षेत्रफल, उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक) और स्वामित्व की स्थिति का विस्तृत डेटा शामिल होगा। अधिकारियों का दावा है कि 29 इससे न केवल नई संपत्तियों की पहचान होगी बल्कि उन खातों का भी पता चलेगा जो अब तक निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। खासकर गांवों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां संपत्तिकर खाते अब तक खुले ही नहीं हैं। बिजली कनेक्शन के आधार पर जांच-नगर निगम का राजस्व विभाग इस समय बिजली कनेक्शन के आधार पर भी संपत्तियों की जांच कर रहा है। अनुमान के अनुसार शहर में करीब 1.5 लाख कमर्शियल बिजली कनेक्शन हैं, जबकि संपत्तिकर के कमर्शियल खाते लगभग 78 हजार ही दर्ज हैं।

शिक्षकों के मनचाहे तबादलों से मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त हटी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता हटा दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के बजाय समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका की प्रति या अन्य उपयुक्त दस्तावेज जमा कर सकेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है और वे आवेदन नहीं कर पा रहे थे। 6 जून को जारी तबादला नीति में विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का जिक्र नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी बताया जा रहा था। इस कारण बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं परेशान थे। मुद्दा सामने आने के बाद विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर नियम स्पष्ट कर दिया। मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या दूर होने के बावजूद स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीतिगत दिक्कतें बनी हुई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि होने के बावजूद कई शिक्षक आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक संगठनों के अनुसार 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध और तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक पहले ही प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं।

राहत की बजाए बनी परेशानी

स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्वैच्छिक तबादला नीति शिक्षकों के लिए राहत के बजाय परेशानी बनती जा रही है। तबादला पोर्टल में कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिससे हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पति-पत्नी के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों को हो रही है।

न्यूज ब्रीफ

गो सम्मान आह्वान अभियान का बना विश्व रिकॉर्ड ,5.25 करोड़ हस्ताक्षर

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● 27 अप्रैल 2026 को देशभर के 5,000 से अधिक तहसील मुख्यालयों पर आयोजित इस अभियान में 5.25 करोड़ से अधिक गौभक्तों, संतों एवं नागरिकों के हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपे गए। इस उपलब्धि को 'विश्व का सबसे बड़ा बहु-स्थान जन-हस्ताक्षर एवं ज्ञापन अभियान' घोषित कर स्वर्णिम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर संत समुदाय को संस्थापक वीरेंद्र कुमार जैन एवं डायरेक्टर रेखा जैन ने सम्मानित किया। संत अच्युतानंद जी महाराज ने कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है तथा गौसंरक्षण के लिए समाज की व्यापक भागीदारी आवश्यक है।

मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन ने इंडियन इनोवेशन आइकॉन्स 2027 के लिए मांगे आवेदन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● प्रभावशली नवाचार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में में अग्रणी मैरिको इनोवेशन फ़ाउंडेशन (एमआईएफ) ने आज अपने प्रमुख द्विवार्षिक मंच इंडियन इनोवेशन आइकॉन्स के 11वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए। वर्ष 2006 में शुरू किया गया 'इंडियन इनोवेशन आइकॉन्स' आइकॉन्स आज देश के अग्रणी नवाचार सम्मान मंचों में से एक बन चुका है। यह ऐसे भारतीय नवाचारों को पहचान और प्रोत्साहन देता है, जो फिलहाल अपेक्षाकृत कम चर्चित हैं, लेकिन सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्तर पर देश मे बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।

हितग्राही समस्या समाधान शिविर 25 जून को

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री ओम जैन के मार्गदर्शन में इंदौर शहर की विभिन्न मंडल कॉलोनियों के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हितग्राही समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र इंदौर द्वारा यह शिविर 25 जून 2026 (गुरुवार) को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ए.बी. रोड स्थित मंडल कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंदौर में आयोजित किया जाएगा। शिविर में अध्यक्ष श्री ओम जैन की उपस्थिति में मुख्यालय भोपाल एवं वृत्त इंदौर के अधिकारी-कर्मचारी हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करेंगे।

आयुक्त क्षितिज सिंघल ने किया औचक निरीक्षण, पानी की क्लोरीन टेस्टिंग की

भागीरथपुरा में पेयजल की शुद्धता की कराई जांच, बारिश में सतर्कता जरूरी

ड्रेनेज और पाइपलाइन कार्यों का लिया जायजा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार सुबह भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा कर पेयजल व्यवस्था, ड्रेनेज और पाइपलाइन कार्यों के बाद चल रहे सड़क निर्माण एवं रेस्टोरेशन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें तय समयसीमा में तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त आशीष पाठक, जोनल अधिकारी आनंद रैदास, जलप्रदाय विभाग के कार्यपालन यंत्री सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने उन सड़कों का जायजा लिया जहां पेयजल और ड्रेनेज लाइन बिछाने के बाद पुनर्निर्माण एवं रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है।

आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों के कारण नागरिकों को अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए। विद्यालय परिसर पेयजल आपूर्ति

अफसरों को नियमित जांच के दिए आदेश

जल गुणवत्ता को लेकर गंभीरता दिखाते हुए आयुक्त ने मौके पर ही पेयजल की क्लोरीन टेस्टिंग कराई। परीक्षण के माध्यम से जल की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से क्लोरीन टेस्टिंग और जल गुणवत्ता परीक्षण किए जाएं, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। आयुक्त ने कहा कि पेयजल आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जल गुणवत्ता की सतत निगरानी रखने और मानसून के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आवागमन को सुगम बनाया जाए। निरीक्षण के दूसरे चरण में आयुक्त ने भागीरथपुरा स्थित पानी की टंकी, शासकीय विद्यालय परिसर पेयजल आपूर्ति और साफ-सफाई व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के रहवासियों से सीधे संवाद कर जलप्रदाय संबंधी समस्याओं और निगम की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। स्थानीय नागरिकों ने नियमित जलापूर्ति और क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

खजराना में लगाई चौपाल- रहवासियों से पूछा हाल

नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को खुदा बख्श कॉलोनी और हबीब कॉलोनी का दौरा कर जलप्रदाय, सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों से लगातार संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। आयुक्त ने क्षेत्र में पेयजल वितरण व्यवस्था, ड्रेनेज लाइनों की स्थिति और साफ-सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ अपर आयुक्त आशीष पाठक, कार्यपालन यंत्री नरेश कुमार भास्कर, जोनल अधिकारी मोहित मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बिया फोडलेला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आयुक्त ने कहा कि ड्रेनेज व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने रहवासियों से संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया।

अवंतिका गैस लाइन फटी, 3 राहगीर झुलसे, गैस सप्लाय हुआ ठप

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● विजयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड 31 के सुमन नगर स्थित जैन मंदिर के पास मंगलवार को अवंतिका गैस पाइप लाइन फट गई। इसके क्षतिग्रस्त होने से गैस का रिसाव शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग लग गई। हादसे में महिला सहित तीन राहगीर झुलस गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार... जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पार्षद बालमुकुंद सोनी द्वारा बोरिंग कराया जा रहा था। इसी दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंच गया। लाइन फटने से गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ समय बाद रिसाव वाली गैस में आग लग गई, जिससे विस्फोट जैसी स्थिति बन गई।

तेज धमाके से दहशत में आए लोग-प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाईदी। अचानक हुए धमाके से आसपास के लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछदेर के लिए पूरे क्षेत्र में दहशत और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हादसे में झुलसे तीन राहगीर-जिनी झाला, सुभाष ठाकुर और गोपाल मालाकार झुलस गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

अटूट आस्था, सामाजिक एकता और उत्साह का अद्भुत संगम, इंदौर में भव्य महेश नवमी प्रभात फेरी संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● महेश नवमी के पावन अवसर पर गोराकुंड स्थित महेश चौक से विशाल प्रभात फेरी का शुभारंभ हुआ। यह भव्य यात्रा खजूरी बाजार, पीपली बाजार, जवाहर मार्ग, नरसिंह बाजार, शीतला माता बाजार होते हुए श्री जानकीनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री महेश एवं श्री जानकीनाथ जी की महाआरती के साथ इसका भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर इंदौर के लोकप्रिय एवं यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, भाजपा नगर उपाध्यक्ष एवं महापौर प्रतिनिधि श्री भारत पारख जी तथा माहेश्वरी समाज की सक्रिय जनप्रतिनिधि एवं पार्षद श्रीमती बरखा नितिन मालू जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते हुए समाजजनों को महेश नवमी की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

यूजी-पीजी एडमिशन का अंतिम दौर, 60 दिन में एडमिशन कैंसिल करवाने पर फीस वापस मिलेगी

सर्वर डाउन, ट्रांजेक्शन फेल जैसी समस्या बनी सिरदर्द

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यूजी-पीजी में एडमिशन का अंतिम दौर चल रहा है। एडमिशन के साथ-साथ सीट छोड़ने यानि एडमिशन कैंसिल करवाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 60 दिन के अंदर प्रवेश निरस्त करवाने पर छात्रों को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा। इसके बाद फीस नहीं लौटेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यूजी-पीजी में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया भले ही पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई हो, लेकिन इंदौर सहित पूरे मध्यप्रदेश के कई छात्र फीस जमा करने से लेकर रिफंड तक में उलझ रहे हैं। सर्वर डाउन, ट्रांजेक्शन फेल जैसी समस्या छात्रों के लिए सिरदर्द बन गई है।

यूजी में आवंटित हुई सीट, पीजी के सीटों का आवंटन आज

यूजी में सीएलसी पहले चरण के तहत सीटों का आवंटन मंगलवार को जारी किया गया। अब आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरु हो गई है जो कि 30 जून तक चलेगी, जिसके बाद ही प्रवेश मान्य रहेगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। वहीं पीजी सीएलसी पहले चरण के सीटों का आवंटन 24 जून को किया जाएगा। 24 से 30 जून के बीच फीस जमा करना रहेगी।

एक्सपर्ट एसएस रघुवंशी ने बताया कई विद्यार्थी दो से तीन कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। जब उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलता है तो वे दूसरे संस्थानों को छोड़ देते हैं। असली परेशानी तब आती है, जब छात्र पूरी फीस जमा कर देते हैं और बाद में कॉलेज फीस लौटाने में आनाकानी करते हैं। मप्र उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 60 दिन के अंदर अगर छात्र पोर्टल पर जाकर एडमिशन कैंसिल करवाता है तो उसे जमा की गई पूरी फीस वापस मिलेगी।

एक्सपर्ट के अनुसार सबसे बड़ी समस्या पेमेंट फेल होने की है। कई छात्रों का पैसा खाते से कट जाता है, लेकिन पोर्टल पर पेमेंट फेल दिखाता है। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ट्रांजेक्शन फेल होने पर राशि उसी खाते में लौट जाएगी, लेकिन एडमिशन सुरक्षित नहीं माना जाएगा। छात्रों को तय समय में दोबारा फीस जमा करना रहेगी, वरना नाम प्रवेश सूची से हट जाएगा। अंतिम तारीख पर सर्वर धीमा होने से कई छात्र दोबारा फीस नहीं भर पा रहे।

ओटीपी और लॉगिन की दिक्कत: ग्रामीण इलाकों के छात्रों को पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी हो रही है पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी नहीं आना, पासवर्ड रिसेट न होना और बार-बार सेशन एक्सपायर होना आम शिकायत है। इस साल प्रवेश निरस्तीकरण और शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। छात्र पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। पंजीकृत मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा।

तेज बारिश में भी चाणक्यपुरी चौराहे पर डटे रहे बुजुर्ग प्रहरी श्याम बिहानी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● बीती रात जब आसमान से आफत की बारिश बरस रही थी और लोग सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे, ठीक उसी वक्त शहर के चाणक्यपुरी चौराहे पर फर्ज की एक अनूठी मिसाल देखी गई। उम्र के इस पड़ाव पर भी बुजुर्ग यातायात प्रहरी श्याम बिहानी सड़कों पर भरे पानी और मूसलाधार बारिश के बीच मुस्तैदी से खड़े होकर ट्रैफिक संभालते नजर आए। उन्हें इस तरह भीगते हुए पूरी शिद्दत से ड्यूटी निभाते देख वहां से गुजर रहे कुछ आम राहगीरों का दिल भी पसीज गया। बिहानी जी के इस अद्भुत जज्बे से प्रेरित होकर कुछ युवा और नागरिक भी अपनी गाड़ियां किनारे लगाकर उनके साथ आ मिले और बिगड़ते यातायात को सुचारू बनाने में हाथ बंटाने लगे।

पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए-आठवले

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। बीते 12 वर्षों में भारत भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त और मेक इन इंडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत आज चौथे क्रम पर है। श्री आठवले मंगलवार को रेसीडेंसी कोठी इंदौर पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने कई बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, इससे भारत के वर्ष 2047 में विकसित भारत के सपने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं और चार करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं। साथ ही 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय निर्माण से नारी का सम्मान बढ़ा।

इंदौर पुलिस के 'सुपर कॉप्स' सम्मानित : 30 लाख की लूट सुलझाने वाली टीम समेत 58 जवानों को मिला इनाम

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● अपराध नियंत्रण, बेहतर पुलिसिंग और जनसेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय में सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 58 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कमिश्नरेट की मासिक मूल्यांकन प्रणाली में मई माह के प्रदर्शन के आधार पर एसीपी मल्हारगंज कार्यालय ने सभी 12 एसीपी कार्यालयों में पहला स्थान हासिल किया।

क्वींस कॉलेज की मेधावी छात्राओं का भव्य 'अभिनंदन'

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● क्वींस कॉलेज परिसर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) परीक्षा सत्र 2025- 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के सम्मानार्थ एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती वर्षा जैन, पूर्व प्राचार्या श्रीमती गीता सोमशेखरन तथा समस्त संयोजिकाओं द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं माँ सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। समारोह का प्रमुख आकर्षण कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की मेधावी छात्राओं को उनके अभिभावकों सहित ट्रॉफी एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कक्षा दसवीं में तरंग काकानी ने 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सिटी टॉपर, ए.आई.आर.-3 तथा विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किंजा आडवाणी ने 99.2 प्रतिशत अंक अर्जित कर द्वितीय तथा लविशी सोलंकी ने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

बिजली कंपनी के लाइनमैन अब 62 साल में रिटायर्ड होंगे, संविदा वालों को ग्रेजुअटी मिलेगी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● बिजली वितरण कंपनी के अधीन भर्ती हुए लाइन कर्मचारी मौजूदा 55 वर्ष की आयु की बजाए अब 62 वर्ष तक सेवाएं दे सकेंगे, संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों को ग्रेजुअटी प्रदान की जाएगी, साथ ही बिजली चोरी पकड़वाने वाले सूचनादाता को पारितोषिक भी दिया जाएगा। ये अनुमोदन मंगलवार दोपहर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोलोग्राउंड इंदौर स्थित सभागार में निदेशक मंडल की मिटिंग में लिए गए। इस मिटिंग की अध्यक्षता मप्र ऊर्जा विभाग के सचिव एवं कंपनी के चेयरमैन श्री विशेष गढ़पाले ने की। इस मिटिंग में कंपनी गठन के बाद भर्ती हुए लाइनमैनों की मौजूदा रिटायरमैंट आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर सभी कर्मचारियों के समान 62 वर्ष करने का, संविदा कार्मिकों को अन्य कर्मचारियों के समान भर्ती दिनांक से नियमानुसार ग्रेजुअटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बिजली चोरी, अनियमताएं रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार वी कनेक्ट एप के माध्यम से चोरी, अनियमितता की सूचना देने वालों को डीबीटी पद्धति से पारिषोषकि यानि प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ।

देपालपुर तहसील कार्यालय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

तहसील स्तर पर संचालित राजस्व न्यायालयों में सीमांकन, नक्शा बटांकन, नामांतरण, आपसी बंटवारा तथा अवैध कब्जाधारियों से भूमि का कब्जा हटाने जैसे प्रकरणों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, किंतु देपालपुर तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर आम नागरिकों एवं हितग्राहियों के मध्य गंभीर असंतोष व्याप्त है प्राप्त शिकायतों एवं जनचर्चाओं के अनुसार अनेक प्रकरण, जिनका निराकरण एक से तीन माह की अवधि में संभव है, वे अनावश्यक रूप से दस से बारह माह अथवा उससे भी अधिक समय तक लंबित रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप आम नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट का सामना करना

पड़ता है। यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कुछ विशेष प्रकरणों को प्राथमिकता देकर शीघ्र निपटाया जाता है, जबकि अन्य प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है। यदि ऐसे आरोप सत्य हैं, तो यह राजस्व प्रशासन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

कई बार यह भी देखने में आता है कि राजस्व संबंधी विवादों का प्रारंभिक स्तर पर समाधान संभव होने के बावजूद पक्षकारों को अनावश्यक रूप से जटिल प्रक्रियाओं में उलझा दिया जाता है, जिससे विवाद और अधिक गहरा हो जाता है। ऐसी स्थिति न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा यह शिकायत भी की जाती रही है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का वास्तविक एवं प्रभावी निराकरण किए बिना ही उन्हें पोर्टल पर निराकृत प्रदर्शित कर दिया जाता है। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की भावना के प्रतिकूल है।

जनसुनवाई में सुनी गई आमजन की समस्याएं, जरूरतमंदों को मिली राहत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, भरण-पोषण, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद एवं अन्य विभागों से जुड़े अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, बुधवार 24 जून 2026

न्यूज ब्रीफ

दिगंबर जैन खरौआ समाज का मिलन समारोह संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्री दिगंबर जैन खरौआ समाज का जून माह का मिलन समारोह रविवार को एक्वा इमैजिका वाटर पार्क में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष श्री नवीन जी जैन ने की। कार्यक्रम में समाज के लगभग 300 सदस्य परिवार सहित सम्मिलित हुए। बच्चों, युवाओं एवं वरिष्ठजनों ने एक साथ वाटरपार्क का आनंद उठाया और मनोरंजक खेलों में सहभागिता की। समाज पदाधिकारी राहुल जैन ने बताया कि इस मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी, परिवारों और समाजजन को आपसी सौहार्द के साथ जोड़कर रखना है। खरौआ जैन समाज द्वारा इस प्रकार के मिलन समारोह समय-समय पर आयोजित किए जाते रहते हैं, ताकि सामाजिक एकता और परस्पर संवाद को बढ़ावा मिल सके। समारोह में उपस्थित सभी सदस्यों ने आयोजन की सराहना की और इसे सामुदायिक जुड़ाव का एक प्रेरणादायी प्रयास बताया।

संसार के रिश्ते वैभव, पैसा और ऐश्वर्य देखकर बनते हैंलेकिन श्याम बाबा सहारा बनते हैं हारे हुए लोगों का

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● खाटू वाले श्याम बाबा की हर बात निराली है। दुनिया में लोग ताकत, पैसा और ऐश्वर्य देखकर अपने रिश्ते बनाते हैं लेकिन खाटू वाले श्याम बाबा तो हारे हुए लोगों की मदद के जरिए अपने रिश्ते बनाते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में श्याम बाबा की गिनती होती है। भगवान की नजरों से हमारा कोई भी कर्म बच नहीं सकता और बिना कर्मफल से बचे कोई रह नही सकता। बर्बरीक ऐसे ही अवतारी देव हैं जिन्हें खुद भगवान कृष्ण ने देवत्व प्रदान किया है। ये दिव्य विचार हैं दिल्ली के प्रख्यात भागवताचार्य पं. संजय प्रभाकर के, जो उन्होंने मंगलवार को एयरपोर्ट रोड, अंबिकापुरी स्थित श्री खाटू श्याम धाम मंदिर के 29वें वार्षिकोत्सव में चल रही श्याम भागवत के दौरान व्यक्त किए। महामंडलेश्वर स्वामी गोपालदास महाराज के सानिध्य में अ.भा. खाटू श्याम अखाड़े के अनेक संत-विद्वान इस महोत्सव में शामिल होने आए हुए हैं। कथा में पं. संजय प्रभाकर ने स्कन्द पुराण के अनुसार नवधा भक्ति एवं शबरी की कथा भी सुनाई और कथा प्रसंग के अनुसार मंदिर परिसर में ध्वजा यात्रा भी निकाली गई। कथा शुभारंभ के पूर्व व्यास पीठ का पूजन समाजसेवी विष्णु बिंदल, मनीष गुप्ता, ममता सोनी, मीना सोनी, संतोष ठाकुर, चावड़ा, संतोष कुमावत, संतोष शास्त्री, सुनीता शर्मा, सविता शर्मा ने की।

प्रदेश भाजपा ने सीएम पर लगे जमीन के सौदे के आरोपों को नकारा

भोपाल (एजेंसी) ● भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस के षडयंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकप्रिय नेता हैं और प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में दिन-रात काम कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आरोपों में सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा साल 2023 में जो नामांकन दाखिल किया गया उसके मुताबिक उस वक्त उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, वो साल 2026 में भी उतनी ही है। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक सिद्धि विनायक कंपनी, जिसका आरोप में जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घटकर मात्र 65 एकड़ रह गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साल 2017 में इसके डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था।

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव के पास भी 2023 से पहले जो 16 एकड़ जमीन थी, उसमें डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया। ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने से पहले की थी। उनकी बहू शालिनी यादव द्वारा 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो मास्टर प्लान एरिया के बाहर की थी। आरोपों में जिन रिश्तेदारों का जिक्र किया गया है। वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदारों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में यह आया है कि रिश्तेदारों पर भी जो आरोप लगाए गए, उसमें भी दिए गए तथ्य गलत हैं। मुझे बताया गया है कि ये रिश्तेदार भी अपनी बात कहेंगे और कार्रवाई करेंगे।

कांग्रेस ने रची मोहन यादव के खिलाफ साजिश-भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस प्रदेश को विकसित बना रहे हैं। चाहे किसानों की बात करें, चाहे उद्योगों के विकास की बात करें, सीएम डॉ.यादव इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी षडयंत्र रच रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब-जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, या मोहन यादव हों, कांग्रेस ने उनके खिलाफ षडयंत्र करके , उनको कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी सख्ती के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं। कांग्रेसी कामों में उन्हें पीछे नहीं कर सके तो इस तरह का षडयंत्र कर रहे हैं। इसे प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

सहायक संचालक मल्होत्रा बने इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी

इंदौर ● मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा 23 जून को जारी किए गए स्थानांतरण आदेशानुसार इंदौर जिला शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक संचालक शौर्य मल्होत्रा को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिए जाने पर शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) के जिलाध्यक्ष दिनेश परमार सहित महेंद्र भारद्वाज, राजेश मालवीय, महेन्द्र पाठक आदि पदाधिकारियों ने हर्ष जताकर बधाई दी है।

अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के चुनाव की मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● अग्रवाल समाज की शीर्ष संस्था श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी गोपालदास अग्रवाल एवं उनके सहयोगी चुनाव अधिकारी मनीष खजांची एवं अरविंद अग्रवाल वेल्यूअर ने मंगलवार को केंद्रीय समिति के आंचल नगर स्थित हाइटेक कार्यालय पर मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन कर दिया है। सदस्यों से मतदाता सूची में सुधार और संशोधन के लिए 26 जून तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

आपातकाल की विभीषिका विषय पर व्याख्यान कल

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, टोली संयोजक महेश कुकरेजा, राकेश शर्मा और सीटू छाबड़ा ने बताया कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब वर्ष 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की हत्या की थी। भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। कल 25 जून को आपातकाल की 51 वीं बरसीं है, भाजपा द्वारा आपातकाल के काले अध्याय से युवाओं को परिचित कराने के उद्देश्य से आपातकाल की विभीषिका विषय पर 25 जून को शाम 4 बजे शुभकारज गार्डन में व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। व्याख्यान में भाजपा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सोलंकी कॉंग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल पर प्रकाश डालेंगे। नेताओं ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, जिससे बौखलाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकाल लगा दिया, इंदिरा गांधी सरकार ने लाखों लोकतंत्र सेनानियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। कॉंग्रेस ने सारी हदें पार कर दी, लोकतंत्र का गला घोट दिया।

स्मृति नगर में नवीन संत - सदन का लोकार्पण समारोह

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● दिगंबर जैन समाज स्मृति नगर की श्रद्धा , सेवा एवं सामूहिक समर्पण से निर्मित नवीन संत सदन का लोकार्पण समारोह पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी एवं अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। उक्त भवन का शिलान्यास समाधिस्थ संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से हुआ था।

दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के प्रचार प्रमुख सतीश जैन ने बताया कि आज रविवार को प्रात: 6:00 बजे से जाप्यानुष्ठान , श्री जी के अभिषेक, शांति धारा, संगीतमय पूजन व शांति विधान हुआ। तत्पश्चात पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि जब स्मृति नगर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण पड़े थे तब इस भवन का शिलान्यास उन्हीं के कर कमलों से हुआ था। आचार्य श्री ने कहा था कि मंदिर निर्माण तो हो जाएगा किंतु चलते फिरते तीर्थों के लिए धाम नहीं बनाया तो वे कहां रुकेंगे। और संतों का चातुर्मास कहां होगा। इस भावना के साथ स्मृति नगर दि.जैन समाज ने आचार्य श्री जी से चातुर्मास का निवेदन किया था। आज उनका वो स्वप्न पूरा हुआ। सतीश जैन ने बताया कि नवीन संत सदन के लोकार्पण कर्ता थे, भरत- कुसुम मोदी परिवार। सहयोगी थे संजय - श्रीमती अर्चना पाटोदी परिवार। शिखर पूंज थे, मनोज बाकलीवाल परिवार एवं महामहिम परिवार थे सिंपल जी - अंकिता जी जैन परिवार।

अवैध पार्किंग, पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शहर में अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल सरवटे बस स्टैंड ओर पटेल ब्रिज के नीचे लंबे समय से अवैध पार्किंग संचालित होने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध पार्किंग खुलेआम चल रही है, इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और पुलिस प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड के बाहर ओर ब्रिज के नीचे बड़ी संख्या में

कारें और अन्य वाहन घंटों खड़े रहते हैं। सूत्रों के अनुसार यहां खड़े होने वाले कई वाहन आसपास के होटलों में ठहरने वाले ग्राहकों के बताए जा रहे हैं। व्यस्त सड़क और बस स्टैंड के समीप इस तरह की पार्किंग से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना रहता है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध पार्किंग स्थल से कुछ ही दूरी पर छोटी ग्वालटोली थाना स्थित है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं होना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पुलिस और पार्किंग संचालकों की कथित सांठगांठ के कारण यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार जारी अवैध पार्किंग व्यवस्था प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर रही है।

कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थिति में सम्पन्न

नई दिल्ली (एजेंसी) ● अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार, 21 जून को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शिरकत की, जबकि अधिवेशन की अध्यक्षता अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप द्वारा की गई।

श्री दत्त देवालय अवधूत मंदिरम में भव्य श्री दत्तात्रेय मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्रीदत्त संप्रदाय में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती (टेंब्ये) स्वामी महाराज के शिष्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री केशवानंद सरस्वती (तांबे) स्वामी महाराज की कुटी सिल्वर ऑक्स कॉलोनी वैशाली नगर तिराहा अन्नपूर्णा रोड़ पर स्थित श्रीगुरु प्रासादिक श्रीदत्त देवालय अवधूत मंदिरम जो श्री केशवानंद सरस्वती आश्रम ट्रस्ट द्वारा

संचालित एवं श्री दत्त माऊली भाविक मंडल द्वारा प्रबंधित है में योगीजनवल्लभ भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु की दिव्य मूर्ति के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन दिनांक 27 जून 2026 से 03 जुलाई 2026 तक संपन्न होगा। यह सात दिवसीय आध्यात्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान धर्म, संस्कृति एवं सनातन परंपराओं के संरक्षण संवर्धन का अनुपम संगम होगा।

पटवारी राजेन्द्र चौधरी का स्थानांतरण हुआ देपालपुर

कोरोना काल में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका

दैनिक इंदौर संकेत

देपालपुर ● नगर के तहसील कार्यालय को मजबूत और भरोसे मंद पटवारी मिला जिला प्रशासन द्वारा पटवारी के स्थानांतरण आदेश पर जिले के कहीं पटवारी को इधर से उधर किया गया आदेश के अनुसार देपालपुर से 9 पटवारीयो का स्थानांतरण किया गया जबकि 10 नए पटवारीयो की पदस्थापन देपालपुर में की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात देपालपुर क्षेत्र में रहे पटवारी राजेंद्र चौधरी का स्थानांतरण पुन देपालपुर में किया गया। तहसील कार्यालय के सबसे भरोसे मंद पटवारी की गिनती में आते हैं। राजेंद्र चौधरी काम के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं किसानों की समस्याओं को तत्काल निराकरण करना चौधरी की पहली प्राथमिकता रही है, इतना ही नहीं कोरोना काल में चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दिन-रात नगर और ग्रामीण क्षेत्र की सेवा करना दुख सुख में किसानों के साथ खड़े रहना उनकी आदत रहि है। इतना ही नहीं देपालपुर में जब अतिवृष्टि हुई, तब एसडीएम रवि वर्मा तहसीलदार शेखर चौधरी के साथ पूरे देपालपुर अनुभाग में गिरोता से घाटाबिल्लोद तक दो दिन तक लगातार इलाके में भ्रमण किया था। बड़ा बांगड़दा में पटवारी रहते वर्ष 2015 में जब सारे पटवारी दो महीने की हड़ताल पर थे इन्होंने मालवांचल के बच्चो के भविष्य के लिए सिंबायोसिस एवं नर्सीमूंजी जैसी

यूनिवर्सिटी को शासकीय भूमि आवंटित करने के लिए लगातार 2 महीने मेहनत की थी साफ और स्वच्छ छवि के कारण इनकी क्षेत्र में पहचान है क्षेत्र में कई अधिकारी आए हैं और गए लेकिन राजेंद्र का तालमेल हमेशा अधिकारियों के बीच मजबूती से रहा है सुबह से शाम तक अपने कार्यालय पर बैठना और आमजन की समस्याओं का निराकरण करना इन्हीं मूल उद्देश्यों के साथ काम करते हैं चौधरी के स्थानांतरण होने से ग्रामीण अंचल में खुशी की लहर है। आदेश आते ही बधाई देते रहे। पटवारी राजेंद्र चौधरी ने भी 24 अवतार मंदिर पहुंचकर लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया साथ ही देपालपुर आते ही मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य में समर्पण राशि भी दी गई। पटवारी चौधरी ने बताया कि मेरी मेरी पहली प्राथमिकता किसनो की समस्याओं को तत्काल निराकरण करना है समय पर उनके काम करना है कोई भी किसान कार्यालय का चक्कर नहीं लगाए समय पर काम हो यही मेरी पहली प्राथमिकता है।

जिला बार को आधुनिक, सुविधायुक्त और अधिवक्ता-केंद्रित संस्था बनाने का संकल्प : खंडेलवाल

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर जिला अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने अधिवक्ता कल्याण, आधुनिक सुविधाओं और बार के संस्थागत विकास को केंद्र में रखते हुए अपना विस्तृत विजन दस्तावेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ अधिवक्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं और कल्याणकारी व्यवस्थाओं का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है। ऐसे में अब बार को नई सोच, आधुनिक दृष्टिकोण और जवाबदेह नेतृत्व की आवश्यकता है। राजेश खंडेलवाल ने कहा कि अधिवक्ता केवल न्यायालयों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवर नहीं हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

सिर्फ कानून बना देने से अपराध पर अंकुश नहीं लग पाएगा, प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू करने की जरूरत

सवाल है कि सुरक्षा एजंसियां अपराध होने के बाद ही हरकत में क्यों आती हैं। अपराध को होने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने की घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि सामाजिक और मानवीय संवदेनाओं को भी झकझोर दिया है। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए विशेष कानून बनाए जाने के बाद भी क्या वजह है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग नहीं पा रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में एक बच्ची को सोमवार तड़के उस समय अगवा कर लिया गया, जब वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। खबरों के मुताबिक, आरोपी कैब चालक ने बच्ची की अस्मिता को तार-तार करने के बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और शव को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के किनारे एक जंगल में फेंक दिया। देश की राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि यहां सुरक्षा व्यवस्था दूसरे शहरों की अपेक्षा बेहतर होगी। मगर यहां आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें, तो स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है। घर हो या फुटपाथ, लोग कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। हैरत की बात है कि बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर देने के बाद भी आरोपी के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह घटनास्थल पर दोबारा आया, लेकिन पुलिसकर्मियों को देख कर वहां से भाग गया। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर अपराधियों के भीतर कानून का डर खत्म हो गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जाहिर है कि सुरक्षा एवं जांच एजंसियों की लापरवाही की वजह से जब अपराधी कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं, तो उनके भीतर किसी तरह का खौफ नहीं रहता है। शासन-प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि सिर्फ कानून बना देने से अपराध पर अंकुश नहीं लग पाएगा, उसे प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू करने की जरूरत है।

काम क्रोध,लोभ,मोह और अहंकार: मानव स्वभाव -आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपदा में अवसर का अर्थ इन नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना

वैश्विक स्तरपर मानव सभ्यता के विकास का इतिहास केवल भौतिक प्रगति का इतिहास नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, प्रवृत्तियों और मानसिक अवस्थाओं के निरंतर संघर्ष,संतुलन और परिष्कार का भी इतिहास है। भारतीय दर्शन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को सामान्यत: पंचविकार कहा गया है। धर्मग्रंथों,संत साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं में इनका उल्लेख ऐसे तत्वों के रूप में किया गया है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकते हैं।किंतु यदि इनका गहन अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि ये भाव स्वयं में न तो पूर्णत: अच्छे हैं और न ही पूर्णत:बुरे। इन पांच विकारों का सदुपयोग करने और उन्हें अवसर में बदलने की अवधारणा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं: काम (इच्छा/उत्साह):इसे वासना के बजाय कुछ बड़ा हासिल करने या उत्कृष्ट लक्ष्य (जैसे रचनात्मक कार्य या समाज सेवा) के प्रति जुनून में बदलें।क्रोध (रोष):इसे दूसरों या स्वयं के विनाश के बजाय, अन्याय और अपनी कमियों के खिलाफ लड़ने की दृढ़ शक्ति में बदलें।लोभ (लालच): भौतिक वस्तुओं के लालच को ज्ञान, अच्छे कर्म, और आध्यात्मिक उन्नति के प्रति लालसा में बदलें,मोह (लगाव): सांसारिक मोह को अपने काम, परिवार और मानवता के प्रति सच्ची प्रेम भावना में बदलें अहंकार (घमंड): इसे मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ के झूठे अहंकार से निकालकर मैं सब कुछ सीख सकता हूँ के आत्मविश्वास में बदलें। वास्तव में ये मानव व्यक्तित्व की स्वाभाविक शक्तियां हैं, जिनका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस उद्देश्य और किस दिशा में किया जा रहा है। यदि इन्हीं भावनाओं को समाज कल्याण,लोक कल्याण, धार्मिक सहायता,सांस्कृतिक संरक्षण और जनहित के कार्यों में नियोजित किया जाए,तो यही पंचविकार मानव उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के साधन बन सकते हैं।भारतीय चिंतन सदैव यह कहता रहा है कि मनुष्य का मूल्यांकन केवल उसके भीतर उत्पन्न होने वाले भावों से नहीं,बल्कि उन भावों के उपयोग और परिणामों से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए काम केवल भौतिक इच्छा नहीं है, बल्कि सृजन की प्रेरणा भी है। क्रोध केवल विनाश का माध्यम नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी बन सकता है। लोभ यदि व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रहे तो हानिकारक है, किंतु यदि वह समाज के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटाने की आकांक्षा में परिवर्तित हो जाए तो विकास का माध्यम बन सकता है। मोह यदि केवल व्यक्तियों तक सीमित न रहकर संस्कृति, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का रूप ले ले तो वह सामाजिक एकता का आधार बन जाता है। इसी प्रकार अहंकार यदि आत्ममुग्धता न बनकर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में परिवर्तित हो जाए तो समाज को दिशा देने का कार्य करता है। इसलिए यह मान लेना कि इन भावों का उदय होते ही व्यक्ति गलत

मार्ग पर चल पड़ा है, एक अधूरी और सतही समझ होगी।

अगर हम इन पांचो विकारों में से किसी एक की तुलना महाराष्ट्र शासन की एक कमेटी के निर्णय से करें तो 17 जून 2026 को महाराष्ट्र में मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति द्वारा 44 मामलों को वापस लेने की सिफारिश इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले 29 सितंबर 2025 को भी 77 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की गई थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सरकार केवल एक बार की कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि एक संस्थागत व्यवस्था विकसित करने का प्रयास कर रही है जिसके माध्यम से ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा की जा सके। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक माना जा सकता है।इन मामलों की प्रकृति पर ध्यानदेना भी आवश्यक है।समिति द्वारा जिन मामलों को वापस लेने की सिफारिश की जाती है,वे मुख्य रूप से गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, श्रमिक आंदोलनों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न वैचारिक या जनहित आंदोलनों से जुड़े होते हैं। ऐसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होती है और कभी-कभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं या स्थानीय परिस्थितियों के कारण मामले दर्ज हो जाते हैं।

यदि इन मामलों में कोई गंभीर आपराधिक मंशा नहीं है और वे केवल सार्वजनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों से संबंधित हैं, तो उनकी पुनर्समीक्षा लोकतांत्रिक न्याय की भावना के अनुरूप मानी जा सकती है।हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट सीमाएं और अपवाद निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हत्या, गंभीर हिंसा, गंभीर मारपीट जैसे जघन्य अपराध तथा व्यक्तिगत या दीवानी विवादों से जुड़े मामलों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों की आड़ में गंभीर अपराधों को संरक्षण न मिले। इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा सकती है। इस समिति का उद्देश्य उन मामलों की पहचान करना है जो मुख्यत: सामाजिक धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के दौरान दर्ज हुए हैं और जिनमें गंभीर आपराधिक तत्व नहीं हैं। समिति के समक्ष आने वाले प्रत्येक आवेदन की गहन जांच की जाती है। इसके बाद जिन मामलों को वापस लेने योग्य माना जाता है, उन्हें पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय समितियों के पास भेजा जाता है, जहां आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि केवल उचित मामलों को ही राहत मिले और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि अधिकांश सामाजिक आंदोलनों,स्वतंत्रता संघर्षों और जनजागरण अभियानों के पीछे मानवीय भावनाओं की प्रबल भूमिका रही है।अन्याय के विरुद्ध क्रोध,समाज के प्रति मोह, परिवर्तन की इच्छा और नेतृत्व का आत्मविश्वास ही बड़े-बड़े आंदोलनों को जन्म देता है।यदि महात्मा गांधी को अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों पर नैतिक आक्रोश न होता,यदि नेल्सन मंडेला कोरंगभेद के विरुद्ध संघर्ष की तीव्र भावना न होती,यदि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सामाजिक समानता के लिए गहरा समर्पण न होता, तो इतिहास की दिशा संभवत: अलग होती। इसका अर्थ यह है कि मानवीय भावनाओं को केवल विकार कहकर नकार देना उचित नहीं है; उन्हें सकारात्मक दिशा देना अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में समाज कल्याण और लोकहित के लिए कार्य करने वाले लोगों को केवल इसलिए अपराधी की तरह देखना उचित नहीं हो सकता क्योंकि किसी आंदोलन या आयोजन के दौरान उन पर मामला दर्ज हो गया था। यदि उनके कार्यों का उद्देश्य समाज की भलाई, सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक आयोजन या जनहित रहा हो और उन्होंने कोई गंभीर अपराध न किया हो, तो उन्हें सुधार और पुनर्विचार का अवसर मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण दंडात्मक न्याय के स्थान पर सुधारात्मक न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है।आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज पंचविकारों को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखने की बजाय उनके सकारात्मक रूपों को भी समझे। जब काम सेवा की आकांक्षा बनता है, क्रोध अन्याय के विरुद्ध संघर्ष बनता है, लोभ समाज के लिए संसाधन जुटाने की प्रेरणा बनता है, मोह संस्कृति और समाज के प्रति समर्पण बनता है तथा अहंकार आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में परिवर्तित होता है, तब यही भाव मानवता के विकास के साधन बन जाते हैं। इसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी केवल कानून का कठोर अनुपालन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिस्थितियों, उद्देश्यों और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण निर्णय लेना भी आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार की समिति द्वारा मामलों की समीक्षा और उपयुक्त मामलों को वापस लेने की सिफारिश इसी संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण है। यह पहल एक ओर कानून के शासन का सम्मान करती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक आयोजकों और जनहित में कार्य करने वाले नागरिकों को अनावश्यक कानूनी बोझ से राहत देने का प्रयास भी करती है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ती है, तो यह लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय और जनसहभागिता के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रभावी मॉडल बन सकती है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है। विभिन्न समुदाय,संगठन और नागरिक समूह समय-समय पर अपनी मांगों,अधिकारों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। गणेशोत्सव नवरात्रोत्सव, दहीहंडी जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से लेकर श्रमिक आंदोलनों,सामाजिक सुधार अभियानों और जनहित प्रदर्शनों तक,नागरिक सहभागिता लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किंतु अनेक बार इन गतिविधियों के दौरान परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि प्रतिभागियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। इनमें से कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें हिंसा, गंभीर अपराध या व्यक्तिगत स्वार्थ का तत्व नहीं होता, बल्कि वे प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन, प्रदर्शन या सामूहिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों से जुड़े होते हैं।यहीं से न्याय और प्रशासन के बीच संतुलन का प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या प्रत्येक ऐसा मामला, जो किसी सामाजिक या धार्मिक गतिविधि के दौरान दर्ज हुआ हो, जीवनभर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहना चाहिए? क्या ऐसे मामलों के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक आयोजकों या जनहित के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों का भविष्य प्रभावित होना चाहिए? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इन प्रश्नों का उत्तर केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी खोजा जाना आवश्यक है। इसी सोच के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की समीक्षा और आवश्यक मामलों में उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया सटीक रूप से प्रारंभ की है। अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जहां शांतिपूर्ण आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाती है। अनेक देशों में यह माना जाता है कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी बात रखने, विरोध दर्ज कराने और सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित होने का अधिकार है। यदि इस प्रक्रिया में ऐसे मामले दर्ज हो जाते हैं जिनमें कोई गंभीर आपराधिक तत्व नहीं है, तो समय-समय पर उनकी समीक्षा लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानी जाती है। -संकलनकर्ता लेखक - **एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं,** गोंदिया, महाराष्ट्र

आंचलिक

ताजिया निर्माण अनुमति विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकारी ताजिया समिति की सदस्यता के दस्तावेज मांगे

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े में मोहर्रम के दौरान ताजिया निर्माण की अनुमति से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सरकारी ताजिया समिति की सदस्यता के दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। याचिका आय्या अंसारी उर्फ जेबरान अंसारी और बाब्बू चाचा उर्फ जाकिर मोहम्मद ने दायर की। इसमें हटवाड़ा के सरकारी इमामबाड़े में मोहर्रम के अवसर पर हर साल 70 दिनों के लिए ताजिया निर्माण की अस्थायी अनुमति देने और परंपरागत किराया या अस्थायी उपयोग शुल्क स्वीकार करने की मांग की गई है। एक अन्य याचिका सिद्दीक द्वारा दायर की गई है। इसमें एसडीओ धार द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के तहत पारित आदेश और आयुक्त इंदौर संभाग द्वारा अपील निरस्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई।

राज्य शासन ने सुनवाई के दौरान बताया कि सक्षम प्राधिकारी पहले ही याचिकाकर्ताओं का आवेदन निरस्त कर चुका है। शासन का तर्क था कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर ताजिया निर्माण की अनुमति मांगने का अधिकार नहीं है। साथ ही, संबंधित स्थल के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े मामलों में पूर्व में निर्णय हो चुके हैं और बेदखली की कार्रवाई भी की जा चुकी है। शासन ने कोर्ट को यह भी बताया कि 17 जुलाई 2025 के आदेश के अनुसार, उक्त स्थल पर ताजिया निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, मोहर्रम के आयोजन के लिए छोटा इमामबाड़ा और जमातखाना को वैकल्पिक स्थल के रूप में उपलब्ध कराया गया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने खुद को सरकारी ताजिया समिति का सदस्य बताया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने उन्हें सदस्यता और अधिकारिता संबंधी प्रमाण पेश करने का अवसर देते हुए मामले की सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी।

एनसीसी शिविर, 750 कैडेट्स ले रहे प्रशिक्षण, 6 जिलों के बच्चों ने ली ड्रिल

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● जिले के बोरावां स्थित जेआईटी परिसर में 36 एमपी बटालियन खंडवा द्वारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप (ष्टञ्जष्ट)-76 का आयोजन किया जा रहा है। 16 जून से शुरू हुआ यह एनसीसी शिविर 24 जून तक चलेगा। शिविर में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा, बुरहानपुर और इंदौर सहित छह जिलों के करीब 750 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करना है। मंगलवार सुबह शिविर में पीटी परेड का आयोजन किया गया। कैडेट्स ने पूरे उत्साह के साथ वार्मअप, स्ट्रेचिंग, दौड़, शारीरिक व्यायाम और सहनशीलता बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने फिटनेस और अनुशासन का परिचय दिया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स को व्यक्ति, समाज और देश सेवा से जुड़ी गतिविधियों के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। शिविर का संचालन कमांड अधिकारी कर्नल के. राजेश के नेतृत्व में किया जा रहा है। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र पांचाल, सूबेदार मेजर राजेंद्र

खत्री और कैंप एडजुटेंट डॉ. एसएस रावत भी प्रशिक्षण गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों के मार्गदर्शन में कैडेट्स को विभिन्न विषयों का व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों में भी कैडेट्स की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। एनसीसी शिविर के माध्यम से कैडेट्स को अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने, टीम के साथ काम करने और नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का अभ्यास भी कराया जा रहा है।

फर्जी जमानत देने वाले आरोपी को भेजा जेल, प्रमाण पत्र में बताया- पहले बेल नहीं दिलाई

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● धरमपुरी न्यायालय ने मंगलवार को अदालत को गुमराह कर फर्जी जमानत दिलाने की कोशिश करने वाले एक जमानतदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। आरोपी अमरसिंह को गिरफ्तार कर उप-जेल भेज दिया गया है।

यह पूरा मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक जैन की अदालत में सामने आया। दरअसल, एक मामले में अभियुक्त राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसे न्यायालय ने 10,000 रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

राहुल की जमानत के लिए ग्राम रणदा (मनावर) निवासी अमरसिंह ने जमानत के कागजात पेश किए। उसने अदालत में एक प्रमाण पत्र देकर यह दावा किया कि उसने पहले कभी किसी अन्य मामले में जमानत नहीं दी है। इसके समर्थन में उसने खेती की जमीन की एक नई पावती भी दिखाई, जिसमें पहले की किसी जमानत का कोई जिक्र नहीं था। जब न्यायालय ने इस मामले में अमरसिंह से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सच बताया। अमरसिंह ने माना कि उसके पास उसी जमीन की एक पुरानी पावती भी है, जिसके आधार पर वह पहले ही दो अलग-अलग मामलों में जमानत दे चुका है। उसने जानबूझकर कोर्ट को धोखा देने और गुमराह करने के लिए यह बात अपने प्रमाण पत्र में छिपाई थी। न्यायालय ने इसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन ने धरमपुरी थाना प्रभारी को आदेश देकर जमानतदार अमरसिंह के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

ट्रांसफर रुकवाने मंत्री सावित्री ठाकुर के नाम का दुरुपयोग

दैनिक इंदौर संकेत

मनावर ● मनावर के सिंघाना स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की अधीक्षक मंजू चौहान पर आरोप लगे हैं। उन पर अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के नाम का तौर पर दुरुपयोग करने का आरोप है। यह मामला 19 जून को सामने आया, जब स्थानांतरण आदेश के बाद एक फर्जी मोबाइल कॉल के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अधीक्षक मंजू चौहान का स्थानांतरण ग्राम खंडलाई हो गया था। इसे रुकवाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर मंत्री सावित्री ठाकुर के नाम से एक व्यक्ति द्वारा प्रभारी प्राचार्य सजन चौहान को अपने फोन से बात करवाई। आरोप है कि फोन पर मंत्री का नाम लेकर स्थानांतरण रोकने के लिए दबाव बनाया गया। इस मामले पर जब अधीक्षक मंजू चौहान से बात की गई, तो उन्होंने आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा, 'मैंने मंत्री के नाम से किसी से भी बात नहीं करवाई है। आप चाहें तो मेरी कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं।' मंजू चौहान ने यह भी बताया कि वह एक विधवा महिला हैं और उनका स्थानांतरण एक छोटे से क्षेत्र में कर दिया गया है, जहां वह असुरक्षित महसूस करेंगी।

सोशल मीडिया चैट और अश्लील वीडियो से घिरा कांस्टेबल

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● जिले के खालवा थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक अफराज मिर्जा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर वायरल चैट, फोटो और वीडियो के आधार पर उस पर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजी गई है, जबकि विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। हिंदूवादी संगठन महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरक्षक अफराज मिर्जा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं और युवतियों से संपर्क करता था। वह अपनी पहचान और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें अपने करीब लाता था और बाद में शोषण करता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ महिलाओं के फोटो और वीडियो का दुरुपयोग कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि पुलिस आरक्षक से जुड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया चैट, फोटो और वीडियो सामने आए हैं जो प्रथम दृष्टया अशोभनीय प्रतीत होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीएसपी खंडवा को सौंपी गई है।

ई-टोकन से परेशान हैं किसान, इस व्यवस्था को समाप्त करें

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खाद वितरण के लिए ई-टोकन प्रणाली लागू की गई है। इससे अधिकांश किसान त्रस्त हैं। उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। एनपीके के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं जिससे लागत बढ़ गई है। साथ ही डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जैसी दैनिक उपयोगी वस्तुओं के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। ब्लाक कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को राज्यपाल के नाम तहसीलदार रमेशचंद्र चौहान को दिए ज्ञापन में यह मांग की है। इससे पहले उन्होंने ई-टोकन का प्रतीकात्मक पुतला भी जलाया। ब्लाक अध्यक्ष संजीव पटेल ज्ञापन में कहा है एनपीके खाद के दामों में वृद्धि से खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। किसानों के लिए खेती करना और परिवार का भरण-पोषण कठिन होता जा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर तुरंत समाधान करना चाहिए।

ओंकारेश्वर झूला पुल बंद, लोडिंग तार की कड़ी टूटी, सुरक्षा के लिए आवागमन रोका

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● ओंकारेश्वर को ममलेश्वर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक झूला पुल मंगलवार देर रात लोडिंग तार की एक महत्वपूर्ण कड़ी (लिंक) टूटने के बाद एहतियातन बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने पुल के दोनों ओर अस्थायी ताला लगाकर आमजन और श्रद्धालुओं के आवागमन पर रोक लगा दी है। मंदिर प्रशासन को मंगलवार रात झूला पुल की कड़ी टूटने की सूचना मिली थी। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 5 बजे प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुल के दोनों प्रवेश द्वार बंद कर दिए और सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। पुल के एक हिस्से में हल्का झुकाव भी देखा गया है। नायब तहसीलदार उदय मंडलोई ने बताया कि झूला पुल की एक कड़ी टूट गई है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुल को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा और रिपेयरिंग पूरी होने के बाद ही पुल को श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा।

विश्व ओलंपिक दिवस पर मैत्री मैच खेलकर पूर्व ओलंपियन की याद मे वृक्षारोपण कर ओलंपिक दिवस मनाए

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● हॉकी इंदौर एसोसिएशन व ताहिर हॉकी ट्रेनिंग सेंटर द्वार आज विश्व ओलंपिक दिवस पर स्थानीय चिमनबाग हॉकी मैदान पर ताहिर हॉकी ट्रेनिंग सेंटर व हॉकी फीडर सेन्टर के बीच एक मैत्री मैच खेला गया जिसमे हॉकी फीडर सेन्टर 1-0 से विजय रहा एंव स्वं पूर्व ओलंपियन को याद कर उनकी स्मृति मे चिमनबाग हॉकी मैदान पर हॉकी इंदौर एसोसिएशन के सचिव किशोर शुक्ला के मुख्य अथिति मे खिलाडियो ने पौधारोपण कर विश्व ओलंपिक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ ए के दास ने की व विशेष अतिथि हॉकी इंदौर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नजमुदीन खुर्शीद थे। इस अवसर पर गुलाम साबिर, अभिषेक यादव, राजपाल सिंह लकी, दीपक यादव, मानसिंह बारिया,जयेश व्यास, नितिश गौड, नवेद अंसारी ,अजय गहलोत, विजय गहलोत, अनमोल शुक्ला,आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर खिलाडियो द्वार प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस पर परिवार के साथ ओलंपिक दिवस मनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के सहसचिव व कोच मो याकुब अंसारी ने किया व अंत मे सेन्टर के कोच अतुल खुणे ने आभार व्यक्त किया।

खामोश रहकर भाव दिखाना सबसे बड़ी चुनौती: सोनाली बेंद्रे

मुंबई (एजेंसी) ● नई वेब सीरीज राख को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस सीरीज में कहानी, माहौल और अभिनय तीनों की काफी चर्चा हो रही है। इस वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का किरदार लोगों का ध्यान खींच रहा है। लंबे समय बाद स्क्रीन पर वापसी करने वाली सोनाली ने इस बार एक ऐसे किरदार को निभाया है जिसमें डायलॉग्स बेहद कम हैं और पूरा अभिनय भावनाओं और खामोशी के जरिए दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि यह किरदार उनके लिए कितना अलग और चुनौतीपूर्ण रहा। सोनाली बेंद्रे ने कहा, मेरे पास काम करने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट था। कहानी ने मुझे इतना मजबूत आधार दिया कि मुझे अपने किरदार को गढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सोनाली ने कहा, मेरे किरदार में डायलॉग्स न होना एक अलग अनुभव था। अब मेरी पहले जैसी याददाश्त नहीं रही, इसलिए लंबे डायलॉग याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस किरदार में इसकी जरूरत ही नहीं थी। मेरे लिए यह बात एक तरह से आसान भी साबित हुई, क्योंकि पूरा फोकस सिर्फ भावनाओं पर था, लेकिन बिना डायलॉग के अभिनय करना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है।

वाइल्ड कार्ड के जरिये विंबलडन में वापसी करेंगी सेरेना

लंदन(एजेंसी) ● सेरेना विलियम्स 44 साल की उम्र में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में वापसी करने जा रही हैं। इसके लिए उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिये प्रवेश दिया गया है। सेरेना ने साल 2022 में खेल से संन्यास ले लिया था। वहीं अब वह चार साल खेल से दूर रहने के बाद फिर से कोर्ट में नजर आयेंगी। पिछले कुछ दिनों से उनकी वापसी की अटकलें थी जो अब सही साबित हुई हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने अपने एक बयान में सब कुछ साफ कर दिया है सेरेना 29 जून से शुरु हो रहे विंबलडन में खेलेंगी। ऑल इंग्लैंड क्लब ने अपने एक बयान में कहा, ''सेरेना को महिला एकल वर्ग में अंतिम वाइल्ड कार्ड दिया गया है।'' सेरेना इस तरह से विंबलडन में एकल और युगल दोनों ही वर्ग में खेलेंगी। उन्होंने पहले ही अपनी बड़ी बहन वीनस के साथ युगल प्रतियोगिता के लिए वाइल्ड कार्ड हासिल कर लिया है।'' डब्ल्यूटीए टूर ने कहा, ''विंबलडन ने महिला एकल वर्ग में आठवें और अंतिम वाइल्ड कार्ड को सेरेना के लिए बचाये रखा था। इसी सप्ताह की शुरुआत में बर्लिन में युगल मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह इस फैसले को लेकर दुविधा में हैं। ''सेरेना ने अंतिम समय तक अपने खेलने को लेकर संशय बनाए रखा था, क्योंकि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या वह एकल मुकाबले में वापसी करेंगी तो उन्होंने जवाब दिया था, ''क्या आपको लगता है कि मैं एकल मुकाबले के लिए तैयार हूं.'' अपने करियर में सेरेना ने एकल में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. इनमें से सात विंबलडन खिताब शामिल हैं। उन्होंने युगल में भी वीनस के साथ 14 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनमें से छह विंबलडन में जीते हैं। सेरेना ने 2012 के लंदन ओलंपिक में एकल और युगल में वीनस के साथ दोनों खिताब जीते थे, जब टेनिस प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड क्लब में खेली गई थी।

हरमनप्रीत नंबर चार पर, जेमिमा नंबर पांच पर खेलें : मिताली

मैनचेस्टर (एजेंसी) ●भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने टीम के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव का सुझाव दिया है। मिताली का मानना है कि कप्तान हरमनप्रीत कौर को नंबर चार पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स को नंबर पांच पर उतारा जाना चाहिए। मिताली ने ये बात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार को देखते हुए कही है। इससे सेमीफाइनल में पहुंचने की भारतीय टीम की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें अपने शेष सभी मैच जीतने होंगे। मिताली ने कहा कि अब भारतीय टीक को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मैच भारत के जीतने लायक था, लेकिन अब आगे का रास्ता मुश्किल है। बल्लेबाजी क्रम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, हमने हरमनप्रीत को नंबर 5 पर इतनी देर से बल्लेबाजी करते हुए बहुत कम देखा है। इसलिए, शायद वह नंबर चार पर और जेमिमा नंबर पांच पर आ सकती हैं। उन्होंने जेमिमा को नंबर पांच पर भेजने को लेकर कहा, जेमिमा पहले भी नंबर पांच पर खेल चुकी हैं और वहां उन्होंने काफी रन बनाए हैं।

खुद के निधन की खबर पढ़ी तो तगड़ा झटका लगा था काजल को

मुंबई (एजेंसी) ● अभिनेत्री काजल अग्रवाल की सफलता की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही प्रेरणादायक भी है। अपनी खूबसूरती, दमदार अभिनय और सादगी के दम पर उन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। ऐसा समय भी आया, जब उनकी मौत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह खबर पढ़कर उन्हें बड़ा झटका लगा था। हालांकि, उन्होंने इस पूरे मामले को समझदारी से संभाला और अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। बचपन से ही उन्हें अभिनय और डांस का शौक था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया था। धीरे-धीरे उनका झुकाव अभिनय की ओर बढ़ा और उन्होंने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का फैसला किया। काजल ने साल 2004 में फिल्म क्यूं! हो गया ना से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय की दोस्त दीया मल्होत्रा का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों का रुख किया। तेलुगु फिल्म लक्ष्मी कल्याणम और फिर चंदामामा में काम कर उन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। असली सफलता उन्हें मगधीरा से मिली, जिसने उन्हें साउथ सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। इसके बाद काजल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई बड़ी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया और लगातार सफलता हासिल की। उनकी जोड़ी साउथ के कई बड़े सितारों के साथ पसंद की गई।

उज्जैन संभाग

महाकाल मंदिर में 142 करोड़ रुपए की आय,पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ अधिक आया दान

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●महाकाल लोक बनने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ दान का प्रवाह भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को रिकॉर्ड 142 करोड़ रुपए की आय हुई है, जिसमें केवल दान मद से ही 78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह बीते छह वर्षों में सबसे अधिक दान है और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 27 करोड़ रुपए ज्यादा है। मंदिर समिति के अनुसार दान पेटियों से 62 करोड़ रुपए, नगद काउंटर पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मनी ऑर्डर से 1.23 लाख रुपए, ऑनलाइन माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए, अन्नक्षेत्र से 3 करोड़ 38 लाख रुपए तथा गुप्त दान के रूप में 4 करोड़ 65 लाख रुपए प्राप्त हुए। वहीं लड्डू प्रसादी की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय हुई। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने सोने-चांदी के करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी दान किए हैं। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में करीब तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। पहले जहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर डेढ़ से दो लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मंदिर की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राम मंदिर में दान को लेकर चल रहे विवाद के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक आशीष पलवड़िया ने बताया कि मंदिर में प्राप्त होने वाले दान के संबंध में पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। मंदिर परिसर में कुल 95 दान पेटियां स्थापित हैं, जिनमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में दान करते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु क्यूआर कोड के माध्यम से भी ऑनलाइन दान कर रहे हैं। हर सप्ताह दान पेटियां खोली जाती हैं। इन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणना कक्ष तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद निरीक्षक, सहायक प्रशासक तथा मंदिर समिति के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दान पेटियां खोली जाती हैं। दान की गणना की फोटोग्राफी कराई जाती है और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न होती है। दान की गणना के लिए नियुक्त कर्मचारियों को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें बिना जेब वाले कपड़े या सिली हुई जेब वाले परिधान पहनने के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका न रहे। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले महाकाल मंदिर का क्षेत्रफल 2.82 हेक्टेयर था, जो विस्तार के बाद बढ़कर 47 हेक्टेयर हो गया है। वर्तमान में मंदिर समिति के कुल 306 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों के वेतन के अलावा मंदिर की सुरक्षा, साफ-सफाई, रखरखाव, निर्माण कार्य, पर्व-त्योहारों की व्यवस्थाएं, धर्मशाला, अन्नक्षेत्र, महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान, गोशाला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बड़ी राशि खर्च होती है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि, श्रावण मास, नागपंचमी सहित अन्य प्रमुख पर्वों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अतिरिक्त व्यय किया जाता है। पहले मंदिर का मासिक खर्च करीब 2.5 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 5 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिमाह हो गया है।

पर्यटन बोर्ड द्वारा पंडे-पुजारियों पर टिप्पणी को लेकर विवाद, पुजारी महासंघ ने दी एफआईआर और मानहानि की चेतावनी

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान टूरिज्म बोर्ड की ओर से पंडे-पुजारियों को लेकर की गई टिप्पणी पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कड़ा विरोध जताया है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने संस्था से बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर संस्था के खिलाफ मानहानि और एफआईआर जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महेश पुजारी ने बताया कि टूरिज्म बोर्ड के हवाले से प्रकाशित एक खबर में कहा गया था कि सिंहस्थ के दौरान पंडे-पुजारी श्रद्धालुओं के साथ 'नो-नो' न करें और ड्राइवर मनमानी न करें, बल्कि मुस्कुराकर 'जय महाकाल' बोलें। महासंघ ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए 'पंडे-पुजारी नो-नो' शब्द का स्पष्ट अर्थ बताने की मांग की है।

महेश पुजारी ने कहा कि तीर्थ स्थल और मंदिरों की परंपरा व व्यवस्था में पंडे-पुजारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देशभर से आने वाले श्रद्धालु अपने पारंपरिक पंडों के माध्यम से धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि श्रद्धालुओं के साथ पुजारियों का व्यवहार हमेशा सम्मानजनक और विनम्र रहता है। महासंघ ने अधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। संगठन का आरोप है कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों में कई बार नौसिखिए अधिकारियों और पुलिस व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महासंघ ने कहा कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर कई बार श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिरों तक पहुंचने में परेशानी होती है। आरोप लगाया गया कि भक्तों को दूर से दर्शन करवाकर वापस भेज दिया जाता है और कई श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है। महासंघ ने संस्था को नसीहत देते हुए कहा कि पंडे-पुजारियों पर टिप्पणी करने से पहले अधिकारियों और व्यवस्थाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस बयान को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है।

एमजी रोड नाला निर्माण में देरी, ठेकेदार पर लगा जुर्माना,आयुक्त ने किया निरीक्षण

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने मंगलवार को एमजी रोड पर निर्माणाधीन नाले के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और ठेकेदार को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

आयुक्त दलीप कुमार ने बताया कि बार-बार चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ। इस कारण संबंधित ठेकेदार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना निर्धारित समय-सीमा से 15 से 20 दिन पीछे चल रही है।

आयुक्त ने जानकारी दी कि अगले 2 से 4 दिनों में सुभाष चौक तक सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। निर्माणाधीन नाले का कार्य भी जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एमजी रोड पर नाला निर्माण के कारण बारिश के दौरान स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

हाल ही में हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई थी, जिससे व्यापारियों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। इसी समस्या के मद्देनजर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं आयुक्त के सामने रखीं। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर लोगों को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाएगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पुत्र आकाश को सौंपी विधानसभा एक की जिम्मेदारी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा इंदौर एक पूरी तरह से पुत्र व पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के हवाले कर दी है। यह बात खुद विजयवर्गीय ने शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन तक इंदौर में विविध आयोजनों में कही। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उम्र अब 70 साल हो चुकी है। वह आठवीं बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। साल 2023 के चुनाव में उन्हें टिकट मिलना काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि वह खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन पार्टी के फैसले के चलते उन्हें मैदान में उतरना पड़ा, जिससे उस समय विधायक रहे उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया।

आकाश इंदौर-3 विधानसभा से 2018 में विधायक रह चुके हैं। अब चर्चा यह है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा इंदौर-1 की जिम्मेदारी धीरे-धीरे पूरी तरह आकाश को सौंप रहे हैं। यह संकेत उन्होंने खुद शनिवार और रविवार को अलग-अलग वार्डों में हुए विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों के दौरान दिए। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि इंदौर-1 सीट को लेकर 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से आकाश विजयवर्गीय के लिए मजबूत की जा रही है।

टिकट कटने का अभी भी मलाल-दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का मन टिकट का नहीं था। लेकिन साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के बन रहे माहौल के चलते पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया। कैलाश साल 2018 में ही चुनाव से हट गए थे और तब आकाश को इंदौर तीन से टिकट मिला और वह जीते। लेकिन 2023 में कैलाश को टिकट मिलने से आकाश का टिकट कट गया। इस पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि आकाश ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन पार्टी का फैसला है तो मानना होगा। अब तक वे इंदौर-4, इंदौर-2, महू और इंदौर-1 से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार इंदौर-1 में उन्हें 50 हजार से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस नेता संजय शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे यह सीट और मजबूत मानी जा रही है। अब राजनीतिक चर्चा है कि 2028 के लिए इंदौर-1 में आकाश विजयवर्गीय के लिए जमीन तैयार की जा रही है।

क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अलग-अलग वार्डों के कार्यक्रमों में कहा कि उन्होंने आकाश से कहा है कि वे पार्टी के काम के चलते महीने में करीब 20 दिन बाहर रहते हैं, इसलिए विधानसभा एक का काम अब आकाश संभालें। पहले आकाश ने इसे लेकर मना किया था, लेकिन बाद में बात मान ली। उन्होंने आकाश की तारीफ करते हुए कहा कि वह अमेरिका की टॉप टेन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, संस्कारी हैं और आम लोगों की भाषा में बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे बड़ों के पैर छूते हैं और सभी की चिंता करते हैं। उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं और वे लोगों से सीधे जुड़कर काम करते हैं।

काम करने में मेरे भी गुरु हैं आकाश

विजयवर्गीय ने आगे कहा कि विधानसभा (स्क्कछ्क) का सभी काम आकाश देखते हैं, विधायक निधि से कहां किसे कितना आवंटन होना है, सभी का हिसाब वही रखते हैं। विधानसभा की पूरी प्लानिंग वही करते हैं। इसलिए सभी काम, समस्या के लिए आप सभी उन्हीं से बात किया करो। उन्होंने कहा कि काम करने में वह मेरे भी गुरु हैं। मुझे कोई बोलता है तो दिमाग में रख लेता हूं, लेकिन कोई आकाश को बोलता है तो वह तत्काल मोबाइल निकालकर नोट कर लेते हैं। इसके बाद वह काम के पीछे पड़ जाते हैं, जब तक कि वह हो नहीं जाए। उन्होंने आगे कहा कि आकाश लगातार बैठक लेते हैं और हर वार्ड की समस्या को लेकर बात करते हैं। एक दिन एक ई-रिक्शा में बैठा तो उसने कहा कि यह आकाशजी ने ही दिलवाया है और इसके कारण धंधा कई गुना बढ़ गया है।

कालरा विवाद में जीतू यादव को क्लीन चिट मिलने से बीजेपी में वापसी की उम्मीद

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में चार जनवरी 2025 को हुए पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमले विवाद में तत्कालीन एमआईसी मेंबर और पार्षद जीतू यादव (जाटव) को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद जीतू का नाम हटा दिया है। इंदौर विधानसभा चार की विधायक मालिनी गौड़ के करीबी पार्षद कमलेश कालरा के घर पर 4 जनवरी 2025 को हमला हुआ था। उस वक्त घर में परिवार और बच्चों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी। मामले में आरोप लगा था कि एमआईसी मेंबर जीतू जाटव ने यह हमला करवाया है। वीडियो फुटेज के आधार पर करीब 30 लोगों की पहचान हुई थी, जिनमें से 21 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसी केस में जीतू जाटव का वॉइस सैंपल लिया गया और उन्हें संदिग्ध भी माना गया था। बाद में मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया और पार्टी स्तर पर शिकायतें हुईं। इसी के चलते जीतू जाटव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब पुलिस जांच में साफ हो गया है कि इस पूरे मामले में जीतू जाटव (बीजेपी पार्षद जीतू यादव) की कोई भूमिका नहीं थी और उनका इससे कोई संबंध साबित नहीं हुआ है।

क्या बोली जांच के बाद पुलिस

पुलिस ने मार्च 2025 में इस मामले में चालान पेश कर दिया था। इसमें बताया गया कि कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। शुरुआती जांच में जीतू यादव को भी संदिग्ध माना गया था और उनकी जांच चल रही थी। लेकिन अब जांच में साफ हो गया है कि घटना के दिन जीतू यादव मौके पर मौजूद नहीं थे। वे बाणगंगा इलाके में अवतिंका गैस एजेंसी के एक कार्यक्रम में शामिल थे।

ढीलपोल : कहीं आने-जाने का केवल एक ही रास्ता, तो कहीं अग्निशमन सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम तक नहीं

लाखों रुपए फीस लेने वाले संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे ने देशभर में कोचिंग और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इन संस्थानों को लाखों रुपए फीस के रूप में चुकाते हैं, लेकिन क्या बदले में उन्हें सुरक्षित माहौल भी मिलता है? इंदौर में करीब दो हजार से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं, जहां लाखों विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किसी आपात स्थिति में इन संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं। जांच के दौरान जो तस्वीर सामने आई, वह चिंताजनक थी। कहीं सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था, तो कहीं अग्निशमन सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम तक नहीं मिले। जिन भवनों में छात्र अपने सपनों को साकार करने की तैयारी कर रहे हैं, वहां उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आई।

चैंपियन स्क्वेयर : *भवरकुंआ स्थित चैंपियन स्क्वायर पर लगे 7 फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायरी डेट के मिले। जिसे नगर निगम की टीम ने जब्त कर दिया। वहीं आने का एक गेट और लिफ्ट है। पहली मंजिल पर सेंटर संचालित होता है। दूसरा रास्ता पास में लोहे की सीढ़िया लगी है वहां से जरूरत पड़ने पर जा सकते है।*

1.30 बजे

अनअकेडमी सेंटर : *अनअकेडमी सेंटर पर आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिलने पर इसे सील कर दिया था। यहां विद्यार्थियों ने बताया कि रोज 2 बजे क्लास खत्म होती है, लेकिन आज जल्दी छोड़ दिया। टीम कार्रवाई कर रही है जिसके कारण दोपहर वाली बैच नहीं आई है। यहां आने और जाने के लिए एक ही गेट है। ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट है। दुर्घटना के दौरान लिफ्ट बंद हो जाए तो संकरी सीढ़ियों से बाहर निकलना पड़ेगा।*

दोपहर : 1.40 बजे

शिशुकुंज ने बंद की मेस, विद्यार्थियों से टिफिन लाने को कहा गया

छात्र घर से लाएंगे टिफिन, खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट 3-4 दिन में आने की उम्मीद

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शिशुकुंज स्कूल में पिछले सप्ताह 100 से अधिक छात्रों के बीमार पड़ने की घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन मेस सेवा अगली सूचना तक बंद कर दी है। विद्यार्थियों से घर से टिफिन लाने के लिए कहा गया है। मंगलवार को भी स्कूल में उपस्थिति सामान्य दिनों की तुलना में कम रही। कई अभिभावकों ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें स्कूल नहीं भेजा, जबकि कुछ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक वे स्कूल के भोजन पर भरोसा नहीं कर सकते।

अभिभावकों को जारी सर्कुलर में स्कूल प्रबंधन ने कहा कि पेट दर्द और उल्टी की शिकायतों के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक बीमारी का कोई निश्चित कारण सामने नहीं आया है। स्कूल ने परिसर की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रतिदिन लगभग 3500 छात्र और स्टाफ सदस्य इसी रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हैं। स्कूल प्रबंधन के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और उनके परिवारजन भी यही भोजन करते हैं।

सभी स्कूलों में मेस की जांच होगी उधर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मेस से लिए गए भोजन और दूध के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। खाद्य विभाग के अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के मामलों में दूषित दूध, पानी या अन्य खाद्य पदार्थ कारण हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में पानी की गुणवत्ता संतोषजनक मिली है, इसलिए अन्य खाद्य पदार्थों विशेष रूप से दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट तीन से चार दिन में आने की संभावना है, जिसके बाद बीमारी के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। टीम बुधवार से जिन स्कूलों में मेंस संचालित किया जाता है वहां की जांच करेगी।

जिले के सभी 73 मंडलम में कांग्रेस की कमेटियां गठित

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ने जिले के सभी 73 मंडलम की कार्यकारिणियों का गठन पूरा कर लिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की गई। पिछले कुछ सप्ताह से मंडलम समितियों की सूचियां जारी की जा रही थीं।

अंतिम चरण की नियुक्तियों के बाद अब जिले के सभी 73 मंडलम में कांग्रेस की संगठनात्मक इकाइयां सक्रिय हो गई हैं। पार्टी का कहना है कि इन समितियों के माध्यम से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशों के अनुरूप संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया गया है। अब जिले के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सक्रिय टीम मौजूद है, जो जनसमस्याओं को उठाने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। वानखेड़े ने नवगठित मंडलम समितियों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तत्काल सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को देखते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

कांग्रेसी पार्षद कमिश्नर से मिलकर करेंगे चर्चा

किराए पर स्वीपिंग मशीन और ठेकेदारों को भुगतान नहीं

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● एक बार फिर नगर निगम में हंगामा है और वजह शहर में सड़क की सफाई के लिए किराए पर स्वीपिंग मशीन लेकर सालाना करोड़ों रुपये का भुगतान किराए के रूप में करेंगे। इसके खिलाफ कांग्रेसी पार्षद हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष के साथ एक बार कमिश्नर महापौर से मिलकर इसका विरोध करेंगे।

बताया जा रहा है कि सालाना करोड़ों रुपये का भुगतान करने के स्थान पर खुद की मशीनें खरीद सकते हैं लेकिन नगर निगम ऐसा नहीं कर रहा है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आज ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने के कारण कई प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं या नए टेंडर कोई लेने को तैयार नहीं है। इस विषय में अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन 30 नई स्वीपिंग मशीन ठेके पर चलाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसके खिलाफ कांग्रेसी पार्षद मिलकर विरोध कर रहे हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि

सालोना 30-40 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 5 साल के लिए स्वीपिंग मशीनों को किराए पर लिया जा रहा है। इससे निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि नई मशीनें लेने से नगर निगम के पास खुद ही नई मशीन हो जाएगी और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस विषय में कांग्रेसी पार्षद, एक बार निगम कमिश्नर और महापौर से मिलकर विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं के बिजली बिल की समस्या का नहीं हो रहा समाधान

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● प्रदेश की मोहन सरकार के अफसर ही पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए काम करने को तैयार नहीं है। विभागीय अधिकारी अगर रुचि लेते हैं तो अभी तक बकाया बिजली बिल के लिए सरकार की समाधान योजना पर विचार होता और समाधान भी निकल जाता लेकिन उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों लोक अदालत में भी समाधान के लिए कई लोग पहुंचे परंतु विभाग के ही अफसर नहीं देते हैं ध्यान, सरकार की योजना में नहीं लेते अधिकारी रुचि उनका समाधान होने के बजाय उलझ गए। नतीजा स्थिति आज भी वही है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों के हठधर्मिता के चलते और लापरवाही पूर्ण उपभोक्ताओं से बराबर चर्चा नहीं करने और बार बार नाराजगी जाहिर करने के कारण अब उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर इधर-उधर भटक रहे हैं। समाधान योजना सरकार ने निकाली, जिसमें कहा गया कि बकाया बिल बिजली बिलों को लेकर समाधान होगा और उनका काम होगा, लेकिन आज तक काम नहीं हो रहा है। इसमें उदाहरण इसी से समझा जा सकता है कि एक जोनल कार्यालय व अन्य विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं मिलते हैं। बिजली बिल बकाया के लिये समाधान योजना जो जमा कर रहे उन्हें धक्के खिला रहे है। पश्चिम विधुत वितरण कंपनी बकाया बिलो के लिये समाधान योजना चला रही है और जो जमा करना चाहते उन्हें धक्के खिला रहे है। उपभोक्ताओं द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं एक उपभोक्ता द्वारा भी आरोप लगाया गया है और उपरोक्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता ने संभावित आरोप लगाया है कि शिप्रा की विजिलेंस ने गलत केस बनाया।

भूमाफिया के गुर्गों ने पुलिस पर किया हमला

जवानों के सिर फूटे, मामला दबाया

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में भूमाफियाओं के हौंसले तो पहले से ही बढ़े हुए हैं और अब उनके गुर्गों की हिमाकत इतनी हो गई कि पुलिस को ही पीट दिया। मामला इंदौर के कनाडिया थाने में भूरी टेकरी के पास डायमंड कॉलोनी में हुआ। इंदौर के कनाडिया इलाके में जमीन विवाद को लेकर रविवार रात भारी बवाल हुआ। विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम पर हमला हुआ। नशे में धुत गुंडों ने पुलिस जवानों को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट दिया।

इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी पुलिस अफसर मामले को छुपा रहे हैं। इंदौर में खाकी पर गुंडे भारी पड़ गए। कनाडिया थाना एरिया में रविवार रात को यह घटना हुई, जिसे पूरी तरह से दबा दिया गया। जबकि इसमें तीन से चार जवानों को बुरी तरह चोट आई। सिर पर टांके लगने की बात भी कही जा रही है। लेकिन मामले में पुलिस ने चुप्पी साध ली है और इसे दो पक्षों का विवाद बताकर कन्नी काट रहे हैं।

इस तरह से हुई घटना- डायमंड कॉलोनी में भूमाफियाओं के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। यहां प्लॉट मालिक अपने कब्जे के लिए आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए भूमाफियाओं ने मोहसिन नाम के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है।

मोहसिन जमीन की सुरक्षा कर रहा है। रविवार को जब कुछ लोग वहां पहुंचे, तो मोहसिन और उसके साथियों ने उन्हें पीट दिया। इसके बाद लोगों ने डायल 100 पर सूचित कर पुलिस को बुलाया। मोहसिन और गुर्गों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि सभी नशे में थे तो इन्होंने पुलिस को भी जमकर पीटा। इसमें आशीष शर्मा और विजय सिकरवार के सिर पर गंभीर चोट आई। साथी पुलिसकर्मी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। लेकिन इस पूरे मामले को दबा दिया गया है।

क्या बोल रहे हैं टीआई- कनाडिया टीआई सहर्ष यादव ने द सूत्र को बताया कि इस मामले में पुलिस का कोई संबंध नहीं है और न ही किसी ने पुलिस पर हमला किया। यह दो पक्षों का आपसी विवाद था।

उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलिटन एरिया अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती, आज होगी सुनवाई

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलिटन एरिया को लेकर जारी की गई अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच में आज इस पर सुनवाई होना है।

इसे लेकर एडवोकेट अक्षत पहाड़िया द्वारा याचिका दायर कर इससे जुड़े अनेक कानूनी बिंदु उठाए गए हैं और कहा गया है कि इन बिंदुओं की अनदेखी कर ये अधिसूचना जारी की गई। अन्य बिंदुओं के साथ इसके नाम में इंदौर को उज्जैन के बाद रखे जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास और आवास विभाग ने इस अधिसूचना में शामिल किए गए 16 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया निर्धारित किया है, जिसमें आधा दर्जन जिले शामिल है। इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, शाजापुर और रतलाम की कुल 38 तहसीलें इसमें शामिल की गई, जिनमें 2781 गांव जुड़े हैं। 75 लाख से अधिक की आबादी के मान से मेट्रो पॉलिटन की तैयारी की जा रही है और चार चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। अंतिम रूप से 16000.87 स्क्वेयर किलोमीटर का एरिया लिया गया है और 75.34 लाख आबादी का अनुमान लगाया गया है। इसमें इंदौर का पूरा 100 फीसदी एरिया, जो कि 3901.63 वर्ग किलोमीटर होता है उसे शामिल किया गया है। जबकि उज्जैन का 6097.99 वर्ग किलोमीटर में से 3595.24 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसमें जोड़ा गया है, जो 59 प्रतिशत होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।